

न्यूज डुडे

नीति आयोग का 'मेथनॉल अर्थव्यवस्था' कार्यक्रम ('Methanol Economy' programme):

- इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के तेल आयात में होने वाले व्यय तथा ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन को कम करना है। साथ ही, कोयला भंडार तथा नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट को मेथनॉल में रूपांतरित करना है।
 - मेथनॉल एक निम्न कार्बन-युक्त व हाइड्रोजन वाहक ईंधन है। यह उच्च राख-युक्त कोयले, कृषि अवशेषों तथा ताप-विद्युत संयंत्रों से उत्सर्जित CO₂ और प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है।
- मेथनॉल अर्थव्यवस्था के लाभ
 - पर्यावरण के अनुकूल:
 - ❖ पेट्रोल में मेथनॉल 15 (m15) का सम्मिश्रण, प्रदूषण को 33 प्रतिशत तक कम करेगा। साथ ही, मेथनॉल द्वारा डीजल के प्रतिस्थापन से वायु-प्रदूषण में 80 प्रतिशत से अधिक की कमी आएगी।
 - ❖ सभी आंतरिक दहन इंजनों (Internal Combustion Engines) में मेथनॉल का दक्षता से दहन होता है।
 - यह पेट्रोल और डीजल के साथ-साथ एथेनॉल से भी सस्ता है। इसकी सहायता से भारत वर्ष 2030 तक ईंधन पर होने वाले व्यय को 30 प्रतिशत तक कम कर सकता है।
 - परिवहन क्षेत्र, घरेलू भोजन पकाने के ईंधन और फ्यूल सेल सहित इसके विस्तृत अनुप्रयोग हैं।
 - इसके लिए मौजूदा इंजनों (वाहनों) और ईंधन वितरण अवसंरचना में बहुत कम संशोधन करने की आवश्यकता है।
- मेथनॉल अर्थव्यवस्था के लिए नीति आयोग का रोड मैप
 - वर्ष 2030 तक कच्चे तेल के आयात का 10 प्रतिशत केवल मेथनॉल द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
 - भारतीय उच्च राख युक्त कोयला, आबद्ध गैस (Stranded gas) और बायोमास का उपयोग करके
 - वार्षिक रूप से 20 मिलियन टन (MT) मेथनॉल का उत्पादन 19 रुपये प्रति लीटर की लागत पर किया जा सकता है।



- विभिन्न स्रोतों से मेथनॉल के उत्पादन के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा मेथनॉल अर्थव्यवस्था अनुसंधान कार्यक्रम (Methanol Economy Research Programme: MERP) संचालित किया जा रहा है। इन स्रोतों में भारतीय कोयला तथा ताप विद्युत और इस्पात संयंत्रों आदि से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड शामिल है।
 - DST ने वर्ष 2015 में अपना मेथनॉल और डाई-मिथाइल ईथर (DME) कार्यक्रम भी लॉन्च किया था।

वर्ष 1970 से वर्ष 2019 के मध्य चरम मौसमी, जलवायवीय एवं जलीय आपदाओं के परिणामस्वरूप मृत्यु दर तथा आर्थिक क्षति से संबंधित एटलस जारी किया गया

- यह एटलस विश्व मौसम विज्ञान संगठन (World Meteorological Organization: WMO) द्वारा जारी किया गया है। यह एक अंतर सरकारी संगठन तथा मौसम विज्ञान (मौसम और जलवायु), क्रियाशील जल विज्ञान एवं भूभौतिकीय विज्ञान से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है।
- मुख्य निष्कर्ष:
 - इस दौरान मौसम, जलवायु तथा जलीय आपदाओं के कारण लगभग 11,000 से अधिक आपदाएं घटित हुईं। इनमें दो मिलियन लोगों की मृत्यु तथा 3.64 ट्रिलियन डॉलर की आर्थिक हानि हुई है।
 - ❖ इस प्रकार, एटलस के अनुसार, विगत 50 वर्षों में मौसमी, जलवायवीय और जलीय आपदा, लगभग 50 प्रतिशत आपदाओं, 45 प्रतिशत मृत्युओं तथा 74 प्रतिशत आर्थिक क्षति के लिए उत्तरदायी थी।
 - इनमें से 91 प्रतिशत से अधिक मृत्यु विकासशील देशों में हुई है।
 - आपदाओं की संख्या पाँच गुना तक बढ़ गई है। हालांकि, मृत्युओं में बड़ी गिरावट भी दर्ज की गई है।
 - ❖ यह अग्रिम चेतावनी प्रणालियों के कारण संभव हो सका है।
 - मौसम पर्यवेक्षण में अंतराल व्याप्त था। कुल 193 सदस्य देशों में से केवल आधे देशों के पास ही बहु-विपदा समय पूर्व-चेतावनी प्रणालियाँ (multi-hazard early warning systems: MHEWS) विद्यमान हैं।
 - ❖ आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क (वर्ष 2015-वर्ष 2030) ने MHEWS के महत्वपूर्ण लाभों को स्वीकार करते हुए इसे अपने सात वैश्विक लक्ष्यों में शामिल करके इसके महत्व को रेखांकित किया है। (इन्फोग्राफिक्स देखें)।
- सेंडाई फ्रेमवर्क, सदस्य देशों को आपदा-जोखिम के विरुद्ध विकास से प्राप्त लाभों की रक्षा के लिए ठोस कार्यवाही विकल्प प्रदान करता है।

सेंडाई फ्रेमवर्क ने वर्ष 2030 तक प्राप्त किए जाने वाले सात वैश्विक लक्ष्यों की रूपरेखा तैयार की है।

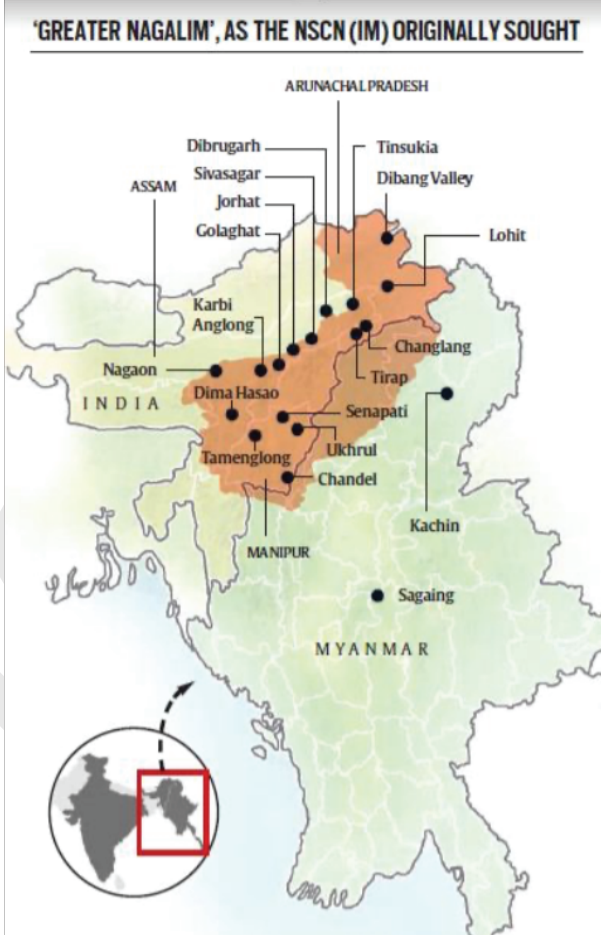


भारत को नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भूमि का विवेकपूर्ण उपयोग करने की आवश्यकता है

- इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस (IEEFA) की एक रिपोर्ट ने इस तथ्य का परीक्षण किया है कि देश को वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन की स्थिति प्राप्त करने के लिए कितनी भूमि की आवश्यकता हो सकती है।
- प्रमुख निष्कर्ष
 - वर्ष 2050 में शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए भूमि उपयोग अनुमान, सौर ऊर्जा के लिए 50,000–75,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र और पवन ऊर्जा के लिए यह 15,000–20,000 वर्ग कि.मी. (कुल परियोजना क्षेत्र) या 1,500– 2,000 वर्ग कि.मी. (प्रत्यक्ष प्रभाव) है।
 - ❖ अर्थात् सौर ऊर्जा के लिए जितनी भूमि की आवश्यकता है, वह भारत के कुल भूभाग के 1.7–2.5 प्रतिशत या गैर-वन भूमि के 2.2–3.3 प्रतिशत के समतुल्य है।
 - इसके साथ ही भूमि का आकार, उसकी अवस्थिति तथा मानव अधिवास, कृषि और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर इसके प्रभाव का भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
- प्रमुख सुझाव
 - अपतटीय पवन, रूफटॉप सोलर और जल निकायों पर सौर (अधिकतर कृत्रिम) को प्रोत्साहन प्रदान करके (जहां विशुद्ध पर्यावरणीय लाभ सुनिश्चित किया जा सकता है) नवीकरणीय ऊर्जा के लिए कुल भूमि उपयोग आवश्यकताओं को कम किया जाना चाहिए।
 - संभावित स्थलों की रेटिंग के लिए सुस्पष्ट पर्यावरणीय और सामाजिक मानदंड विकसित करके, अवांछित क्षेत्रीय संकेन्द्रण को सीमित करके तथा व्यापक रूप से वितरित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का समर्थन करके, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन हेतु भूमि की पहचान एवं आंकलन को अनुकूलित करना चाहिए।
 - भारतीय एग्रीवोल्टिक्स (कृषि भूमि पर खेती के साथ-साथ सौर ऊर्जा उत्पादन) पर अधिक बल दिया जाना चाहिए, जिससे किसानों को लाभ मिल सके तथा अन्य प्रकार की भूमि पर दबाव को कम किया जा सके।

केंद्र सरकार ने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (के) निकी समूह {National Socialist Council of Nagaland (K) (NSCN-K) Niki Group} के साथ संघर्ष विराम समझौता किया

- यह समझौता 8 सितंबर 2021 से 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। इसके अंतर्गत, समूह के 200 से अधिक कैडरों ने 83 हथियारों के साथ शांति प्रक्रिया के तहत आत्मसमर्पण किया है।
- इससे पूर्व सरकार ने वर्ष 2015 में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड-आईएम (NSCN-IM) के साथ नागा शांति समझौते के लिए रूपरेखा समझौते (फ्रेमवर्क एग्रीमेंट) पर हस्ताक्षर किए थे।
- इसके साथ ही, अन्य नागा समूहों जैसे— NSCN-NK, NSCN-R, NSCN-K-खांगो (प्रमुख समूहों NSCN-IM और NSCN-K से पृथक हुए गुट) के साथ संघर्ष विराम समझौते भी किए गए हैं।
- नागा आंदोलन को भारत का सबसे दीर्घावधि तक जारी रहने वाला विद्रोह माना जाता है।
- वर्ष 1946 में, अंगामी फ़िज़ो ने नागा नेशनल काउंसिल (NNC) की स्थापना की थी। इसने 14 अगस्त 1947 को नागालैंड को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया था।
- वर्ष 1975 में NNC ने शिलांग समझौते के तहत हिंसा त्यागने पर सहमति व्यक्त की थी। हालांकि, समूह के भीतर एक गुट ने शिलांग समझौते को अस्वीकार कर दिया और वर्ष 1980 में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (NSCN), का गठन किया। इसने नागालिम अर्थात् ग्रेटर नागालैंड की मांग प्रस्तुत की।
- ❖ नागालिम में "सभी निकटवर्ती नागा-बाहुल्य क्षेत्र" शामिल हैं। इसके अंतर्गत नागालैंड, असम के कई जिले, अरुणाचल प्रदेश तथा मणिपुर के साथ-साथ म्यांमार का एक बड़ा भू-भाग भी शामिल है।
- नागा कोई एकल जनजाति नहीं है, बल्कि यह एक नृजातीय समुदाय है। इसमें कई जनजातियां शामिल हैं, जो नागालैंड राज्य तथा उसके निकटवर्ती भू-भागों में अधिवासित हैं।



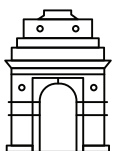
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वस्त्र उद्योग के लिए 10,683 करोड़ रुपये की उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना को स्वीकृति प्रदान की है

- उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना आगामी पांच वर्षों में देश में उच्च मूल्य के मानव निर्मित रेशों (Man-Made Fibre: MMF) के परिधान, MMF वस्त्र और तकनीकी वस्त्रों के दस खंडों या उत्पादों के उत्पादन को प्रोत्साहन प्रदान करेगी।
- वर्तमान में भारत के कुल परिधान निर्यात का पांचवां हिस्सा, MMF परिधान का है।
- तकनीकी वस्त्र खंड में नए युग के ऐसे वस्त्र शामिल हैं, जिनका बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और स्वच्छता आदि सहित अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है।
- ❖ सरकार ने इस क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए अतीत में एक राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन भी आरंभ किया था।
- अन्य विशेषताएं:
 - आकांक्षी जिलों या टियर-3 और टियर-4 शहरों के समीप स्थित कारखानों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस योजना से विशेष रूप से गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना व ओडिशा जैसे राज्यों को लाभ प्राप्त होगा।
 - केवल भारत में पंजीकृत विनिर्माण कंपनियां ही इस योजना में भाग लेने के लिए पात्र होंगी।
- योजना का महत्व
 - वैश्विक वस्त्र व्यापार में महत्वपूर्ण दर्जा प्राप्त करने में भारत की सहायता करना।
 - 7.5 लाख से अधिक लोगों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करना।
 - विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना और वस्त्र निर्यात में वृद्धि करना।
 - वस्त्र उद्योग मुख्य रूप से महिलाओं को रोजगार प्रदान करता है। यह योजना महिलाओं को सशक्त बनाएगी और औपचारिक अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी में वृद्धि करेगी।

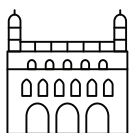
अन्य सुर्खियाँ

 भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य 2+2 वार्ता का आयोजन	○ 10-11 सितंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य प्रथम 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता का आयोजन किया जाएगा। हालांकि, इस वार्ता की सहायता से दोनों देश भारत-प्रशांत क्षेत्र में अपनी साझेदारी को मजबूत करने तथा इस क्षेत्र में चीन की आक्रामकता का प्रतिरोध करने के क्रम में व्यापार संबंधों को व्यापक बनाने की दिशा में प्रयास करेंगे। ➤ 2+2 वार्ता पद का प्रयोग दो देशों के रक्षा और विदेश मंत्रालयों के मध्य संवाद तंत्र की स्थापना हेतु किया जाता है। ○ इस वार्ता के साथ भारत, क्वाड (भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का समूह) में शामिल प्रत्येक देश के साथ द्विपक्षीय वार्ता के इस 2+2 प्रारूप को स्थापित करने में सक्षम हो जाएगा। ○ इसे ऑस्ट्रेलिया-भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की आधारशिला के रूप में भी देखा जा रहा है।
 मुद्रास्फीति पर घरेलू अपेक्षाओं का सर्वेक्षण (Inflation Expectations Survey of Households (IESH))	○ हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने IESH के आगामी दौर की शुरुआत की घोषणा की है। यह मुद्रास्फीति संबंधी अपेक्षाओं और उपभोक्ता विश्वास का आकलन करने पर लक्षित है। यह RBI की मौद्रिक नीति के लिए उपयोगी आगत प्रदान करता है। ○ सर्वेक्षण का उद्देश्य 18 शहरों में लगभग 6,000 परिवारों के व्यक्तिगत उपभोग बास्केट के आधार पर कीमतों में उतार-चढ़ाव और मुद्रास्फीति के संबंध में व्यक्तिपरक आकलन प्रदान करना है। ○ यह सर्वेक्षण परिवारों से मात्रात्मक और साथ ही गुणात्मक प्रतिक्रियाओं की मांग करता है।
 इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट का लोकतंत्र सूचकांक (EIU (Economist Intelligence Unit) Democracy Index)	○ हाल ही में, सरकार ने EIU से इसके भारत में 'लोकतांत्रिक प्रतिगमन' (democratic regression) का दावा करने वाले लोकतंत्र सूचकांक रैंकिंग पर स्पष्टीकरण की मांग की है। ➤ यह सूचकांक पांच श्रेणियों पर आधारित है— चुनावी प्रक्रिया और बहुलवाद, नागरिक स्वतंत्रता, सरकार की कार्यप्रणाली, राजनीतिक भागीदारी एवं राजनीतिक संस्कृति। ➤ इन श्रेणियों के भीतर 60 संकेतकों पर शामिल देशों के प्राप्तांकों के आधार पर, प्रत्येक देश को चार प्रकार के शासनों में से एक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है— पूर्ण लोकतंत्र, त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र, मिश्रित शासन या सत्तावादी शासन। ○ इस वर्ष फरवरी में जारी 2020 रैंकिंग में, भारत को EIU के लोकतंत्र सूचकांक में 53वां स्थान (167 देशों में से) प्रदान किया गया था।
 ICRISAT को अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया	○ अंतर्राष्ट्रीय अर्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान (International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics: ICRISAT) को उप-सहारा अफ्रीका के 13 देशों में खाद्य सुरक्षा में सुधार करने वाले उसके कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है। ○ इसने फलीदार फसलों की एक संपूर्ण श्रृंखला के लिए फलियों की 266 उन्नत प्रजातियां और लगभग आधा मिलियन टन बीज विकसित किए हैं। ○ इनसे लाखों किसानों को मदद मिली है और ऐसी फसलों को जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रत्यास्थ बनाया गया है। ○ ICRISAT एक गैर-लाभकारी व गैर-राजनीतिक संगठन है। यह एशिया और उप-सहारा अफ्रीका के शुष्क क्षेत्रों में विकास के लिए कृषि अनुसंधान को संचालित करता है।
 संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय एजुकेशन रिपोर्ट 2021: 'स्टेडिंग द कोर्स'— द चैलेंजिंग फेसिंग रिफ्यूजी चिल्ड्रन	○ संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय (United Nations High Commissioner for Refugees: UNHCR), संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी है। इसने अपनी रिपोर्ट में शरणार्थी बच्चों और युवाओं के लिए माध्यमिक विद्यालयी शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयास का आह्वान किया है। ○ रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष: ➤ तीन में से दो शरणार्थी बच्चे कभी माध्यमिक विद्यालयों में नहीं जा पाते हैं। ➤ वर्ष 2019-2020 में माध्यमिक स्तर पर शरणार्थियों की सकल नामांकन दर 34 प्रतिशत थी। ➤ वर्ष 2019-2020 में प्राथमिक स्तर पर लगभग 68 प्रतिशत शरणार्थी बच्चों का नामांकन किया गया था। ➤ लड़कियों की शिक्षा तक पहुंच नहीं है।

 सीटी बजाने वाला गांव (Whistling Village)	- पर्यटन मंत्रालय ने मेघालय के कोंगथोंग गांव को विश्व पर्यटन संगठन के "सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों" के लिए नामित किया है। इसे 'सीटी बजाने वाला गांव' (व्हिसलिंग विलेज) भी कहा जाता है। - दो अन्य गांवों को भी नामित किया गया है— तेलंगाना में पोचमपल्ली और मध्य प्रदेश में लघपुरा खास। - सीटी बजाने वाले गांव की एक बहुत ही विशिष्ट परंपरा है 'जिगरवाई इआवबेई'। इसके तहत एक माता अपने शिशु को जन्म के समय उसे नाम की बजाए एक धुन या लोरी से पुकारती है। इसलिए यहां ग्रामीणों के दो नाम होते हैं, एक नियमित नाम और एक गीत का नाम।
 समुद्री साझेदारी युद्धाभ्यास	- भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में किए गए समुद्री युद्धाभ्यास: - भारतीय नौसेना के दो पोतों (INS रणविजय और INS कोरा) ने पश्चिम फिलीपीन सागर में फिलीपींस नौसेना के साथ एक समुद्री साझेदारी युद्धाभ्यास में भाग लिया है। - भारत और वियतनाम की नौसेनाओं ने दक्षिण चीन सागर में आयोजित द्विपक्षीय समुद्री युद्धाभ्यास में भाग लिया है। इस अभ्यास में भारतीय नौसैन्य पोत (Indian Naval Ship: INS) रणविजय और INS कोरा भी शामिल थे।



दिल्ली



लखनऊ



जयपुर



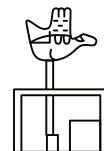
हैदराबाद



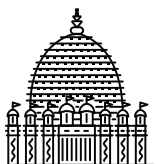
पुणे



अहमदाबाद



चंडीगढ़



गुवाहटी